उससे किसी राज्य को नुकसान हो तो उसकी क्षतिपूर्ति केन्द्र सरकार करती है। तो मध्य प्रदेश सरकार को 618 करोड़ रुपए का कोयले का रॉयल्टी का पुनरीक्षण न करने से जो नुकसान हुआ है, क्या उसकी क्षतिपूर्ति केन्द्र सरकार करेगी? यदि नहीं करेगी तो उसका क्या कारण है?

श्री कड़िया मुंडा: सभापति महोदय, जैसे माननीय सदस्य ने कहा कि 2002 में रॉयल्टी का संशोधन हुआ है और उसके तीन साल के बाद हम फिर से संशोधन करते हैं। अब यह संशोधन करने का समय 2005 में आएगा।

श्री सुरेश पचौरी: सभापति महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा। 1994 के बाद प्रति तीन वर्ष में कोयले की रॉयल्टी का पुनरीक्षण होना चाहिए था। मंत्री जी, आप खुद एक प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे हैं। 1994 के बाद कोयले की रॉयल्टी का पुनरीक्षण नहीं हुआ, जो 1997 में होना था। स्वयं मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि यह 2002 में हुआ। उससे जो मध्य प्रदेश को नुकसान हुआ 618 करोड़ रुपए का, क्या उसकी क्षतिपूर्ति केन्द्र सरकार करेगी? मेरा सीधा प्रश्न यह है कि जिसका उत्तर नहीं मिला।

श्री कड़िया मुंडा: सभापति महोदय, रॉयल्टी की दर को तय करते समय कई बातों का ध्यान रखा जाता है। जो यह बीच में नहीं हुआ, इसके कई कारण हैं, अगर पढ़कर सुनाऊंगा तो बहुत समय लगेगा। मैं माननीय सदस्य को लिखकर भेज दूंगा।

श्री बालकवि बैरागी: माननीय सभापति महोदय, यह सरासर मध्य प्रदेश के साथ अन्याय है। हमें कृपा करके आपका संरक्षण चाहिए।

श्री सुरेश पचौरी: उत्तर ही नहीं आ रहा है।

श्री सभापति: इस अन्याय के बारे में आप दोनों एक साथ खड़े हो गए हैं।

श्री सुरेश पचौरी: माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने यह तो स्वीकार कर लिया है कि प्रति तीन वर्ष जो पुनरीक्षण होना चाहिए था वह नहीं हुआ, लेकिन जो नुकसान हुआ है क्या उसकी क्षतिपूर्ति केन्द्र सरकार करेगी? इसका उत्तर अगर वे अभी नहीं दे सकते हैं तो लिखकर भेजें।

श्री सभापति: ठीक है, आप वह पोजीशन बता दीजिएगा इन्हें। नैक्सट क्वेश्चन।

*252. *[The Questioners Sardar Gurcharan Singh Tohra and Shri Sukhdev Singh Libra were absent. For Answer vide pages 41-42.]*

गैर-सरकारी क्षेत्र में विद्युत परियोजनाएं

*253. **डा॰ कुमकुम राय:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिजली उत्पादन से जुड़ी कितनी परियोजनाएं गैर-सरकारी क्षेत्र में चल रही हैं और क्या इन परियोजनाओं का कार्य निष्पादन सरकार की उम्मीदों के अनुसार नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री अनंत गंगाराम गीते): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) निजी क्षेत्र (कैप्टिव विद्युत संयंत्रों को छोड़कर) में विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की कुल संख्या 44 है। वर्ष 2002-03 तथा 2003-04 (अप्रैल-जून) की पहली तिमाही के दौरान निजी क्षेत्र विद्युत परियोजनाओं द्वारा लक्ष्य की तुलना में उत्पादित विद्युत और उनके कार्य निष्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

विवरण	परियोजनाओं की संख्या	क्षमता (मेगा वाट)	उत्पादन (एम.यू.) कार्यक्रम (निर्धारित लक्ष्य)	वास्तविक	वास्तविक उत्पादन (निर्धारित लक्ष्य का प्रतिशत)
2002-2003					
लाइसेंस	थर्मल-11	3385	21745	22495	103.4
धारक	हाइडल 4	426	1300	1338	102.9
स्वतंत्र	थर्मल-20	4539.3	20884	21561	103.2
विद्युत	हाइडल-7	148.2	659	504	76.5
उत्पादक					
अप्रैल-जून 2003					
लाइसेंस	थर्मल-11	3385	6209	6019	96.9%
धारक	हाइडल 4	426	240	182	75.8%
स्वतंत्र	थर्मल-20	4539.3	6692	5068	75.7%
विद्युत	हाइडल-9	451.2	480	311	64.8%
उत्पादक					

(ग) उत्पादन में कमियों के निम्नलिखित कारण हैं:

(i) कुल प्राकृतिक -गैस विद्युत स्टेशनों पर गैस की कम उपलब्धता।

(ii) तरल ईंधन का अधिक मूल्य, जिसके कारण इन स्टेशनों को कम उत्पादन करने के लिए कहा गया।

हाइडल यूनिटों में कम उत्पादन के लिए उत्तरदायी देश के कई हिस्सों में अपर्याप्त वर्षा।

Power Projects in Private Sector

†*253. SHRIMATI KUM KUM RAI: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) the number of projects for power generation being operated in the private sector and whether performance of these projects is not as per Government's expectations;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF POWER (SHRI ANANT GANGARAM GEETE): (a) to (c) A Statment is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) The total number of power generation projects in private sector (excluding captive power plants) is 44. The details of electricity generated and performance against target by private sector power projects during the year 2002-03 and first quarter of 2003-04 (April-June) are indicated below:

Particulars	No. of Projects	Capacity (MW)	Generation (MU		Actual Generation (% of target fixed)
			Programme (Target fixed)	Actual	
2002-03					
Licensees	Thermal-11	3385	21745	22495	103.4
	Hydel-4	426	1300	1338	102.9
Independent	Thermal-20	4539.3	20884	21561	103.2
Power Producers	Hydel-7	148.2	659	504	76.5

†Original notice of the question was received in Hindi.

Particulars	No. of Projects	Capacity (MW)	Generation (MU Programme (Target fixed)	Actual	Actual Generation (% of target fixed)
April-June, 2003					
Licensees	Thermal-11	3385	6209	6019	96.9
	Hydel-4	426	240	182	75.8
Independent	Thrmal-20	4539-3	6692	5068	75.7
Power	Hydel-9	451.2	480	311	64.8
Producers					

(c) Following are the reasons for the shortfalls in generation:–

(i) Less availability of gas at some of the natural-gas powered stations.

(ii) High price liquid fuel due to which these stations were asked to generate less.

(iii) Inadequate rainfall in many parts of the country accounting for low generation in Hydel units.

डा॰ कुमकुम राय: सभापति महोदय, मेरे इस प्रश्न का मंत्री महोदय ने अधूरा उत्तर दिया है। मैंने सीधा-सीधा प्रश्न पूछा था कि गैर-सरकारी क्षेत्रों में विद्युत परियोजनाओं की संख्या क्या है? इन्होंने उसका उत्तर तो 44 दिया, लेकिन मैंने उसी प्रश्न के दूसरे हिस्से में पूछा था कि कार्य निष्पादन उम्मीदों के मुताबिक नहीं हुआ है क्या? इसके उत्तर में इन्होंने कुछ नहीं बताया है। महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह कहना चाहती हूं कि निजी क्षेत्रों में परियोजनाएं देने के बाद भी, टैरिफ बढ़ाए जाने के बाद भी स्थिति में कोई संतोषजनक सुधार नहीं हो पाया है। एक उदाहरण के रूप में मैं सिर्फ .....(व्यवधान).....

श्री सभापति: आप जब तक उदाहरण देंगी, तब तक समय खत्म हो जाएगा। इसलिए जल्दी पूछिए।

डा॰ कुमकुम राय: यूनिट की दर बढ़ाए जाने के बाद भी बिजली की किल्लत लगातार बढ़ती जा रही है और साथ ही साथ उसकी गुणवत्ता में भी कोई सुधार नहीं हुआ है। बिजली के जितने भी उपकरण हैं, वे बिजली की गुणवत्ता में कमी के कारण बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहती हूं कि बिजली की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए और बिजली की सतत उपलब्धता को बनाए रखने के लिए क्या सरकार ऐसी कोई नीति बनानी चाहती है जिसमें गैर सरकारी क्षेत्र में चलने वाली विद्युत परियोजनाओं को भी शामिल किया जाए?

श्री अनन्त गंगाराम गीते: सभापति, जी, निजी क्षेत्र का जो अनुभव है 9वीं पंचवर्षीय योजना का, उस अनुभव के तहत संतोषजनक उर्जा का निर्माण निजी क्षेत्र से नहीं हो पाया, माननीय सदस्या

सुधार करने की आवश्यकता है और इस गुणवत्ता में सुधार करने के लिए राज्य सरकारों को और उर्जा निर्माण करने वालों को निरंतर सलाह दी जाती है और जो हमारे लोड डिसपैच सैंटर हैं, जहां से इस पर नियंत्रण किया जाता है, उस लोड डिसपैच सैंटर के माध्यम से गुणवत्ता को कायम रखने का प्रयास किया जाता है।

MR. CHAIRMAN: The Question Hour in over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

PMGSY in Arunachal Pradesh

*244. SHRI NABAM REBIA: Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the details of targets fixed for the construction of roads during the Tenth Plan under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana in the State of Arunachal Pradesh; and

(b) the details of roads constructed under the scheme so far in the State?

THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI KASHIRAM RANA): (a) No targets have been fixed for the Tenth Plan period. The road works are cleared on year-by-year basis with reference to the annual allocation for the State.

(b) 122 road works relating to 2000-01 and 27 road works relating to 2001-03 have been reported by the State Government as having been completed.

Clearance for SGPC Members/Employees for trips abroad

*252. SARDAR GURCHARAN SINGH TOHRA:
SHRI SUKHDEV SINGH LIBRA:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether there is any order in force that requires members and employees of Shiromani Gurdwara Prabhandhak Committee (SGPC) to get clearance from Home Ministry before they are allowed to go on a trip abroad;

(b) whether Government are actively considering to review and repeal of such order; and